Research Unit
Press Information Bureau
Government of India

पौष्टिकता को बढ़ावा : स्वस्थ भारत के लिए नि:शुल्क पोषणयुक्त चावल

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

11 अक्टूबर, 2024

"एक समय था जब भारत की खाद्य सुरक्षा एक वैश्विक चिंता का विषय थी, आज भारत वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए समाधान प्रदान कर रहा है।"

~प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कुपोषण से निपटने की आवश्यकता पर बल देते हुए इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से वंचित लोगों को स्वस्थ और समर्थ भारत के निर्माण के लिए पौष्टिक भोजन तक पहुंच का अधिकार है।

इस दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार लोगों के समग्र पोषण कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी सरकारी योजनाओं के तहत पोषणयुक्त चावल वितरित करने के लिए मंत्रिमंडल की हाल ही में दी गई स्वीकृति, कुपोषण मुक्त भारत के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पोषणयुक्त चावल का विस्तार

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) सहित सभी सरकारी कल्याण योजनाओं के तहत पोषणयुक्त चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित को जारी रखने को स्वीकृति दी:

i. पोषणयुक्त चावल पहल को जून 2024 से 31.12.2028 तक बढ़ाया।

ii. भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित एक केंद्रीय पहल के रूप में सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पोषणयुक्त चावल पहल का कार्यान्वयन।

iii. पीएमजीकेएवाई योजना के पहले से स्वीकृत 11,79,859 करोड़ रुपए के आवंटन के तहत पीएमजीकेएवाई (खाद्य सब्सिडी) के एक हिस्से के रूप में पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति की लागत को पूरा करने की वर्तमान व्यवस्था।

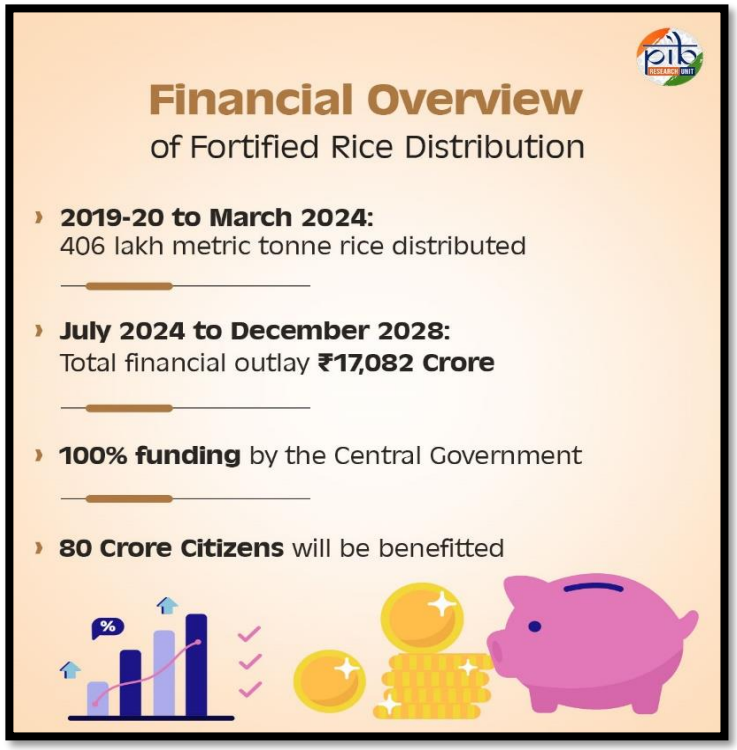

इस पहल का उद्देश्य आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध पोषणयुक्त चावल वितरित करके वंचित वर्ग को बेहतर पोषण प्रदान करना है। इस वितरण के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जाएगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मेटा-विश्लेषण के अनुसार, चावल को पोषणयुक्त बनाने से आयरन की कमी का जोखिम 35 प्रतिशत तक कम हो सकता है। 2,565 करोड़ रुपये के अनुमानित वार्षिक परिव्यय के साथ, इस पहल में प्रति वर्ष 16.6 मिलियन दिव्यांगता-समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) को रोकने की क्षमता है, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 49,800 करोड़ रुपये के बराबर स्वास्थ्य सेवा बचत होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए लागत निहितार्थ नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में एक मूल्यवान निवेश के रूप में देखा जाता है।

2020 में 15 राज्यों में पोषणयुक्त चावल की पायलट योजना के शुभारंभ के बाद से, यह कार्यक्रम उल्लेखनीय प्रगति का साक्षी बना है। 2019-20 और 31 मार्च, 2024 के बीच, लगभग 406 लाख मीट्रिक टन पोषणयुक्त

चावल पीडीएस के माध्यम से वितरित किया गया, जिससे देश भर में लाखों लोगों ने पोषणयुक्त चावल का उपयोग किया है।

पिछले कुछ वर्षों में विस्तार

- **फरवरी 2016:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण और एनीमिया से निपटने के लिए पोषणयुक्त चावल बनाने पर जोर दिया, जिसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जैसे प्रमुख हितधारकों की भागीदारी रही। मंत्रालय द्वारा गठित कार्यबल ने मई 2016 में चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों में चावल को अनिवार्य रूप से पोषणयुक्त बनाने की सिफारिश की गई।
- **मार्च 2018:** नीति आयोग, भारतीय खाद्य निगम और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने आईसीडीएस और मिड-डे मील के लिए चावल और गेहूं के आटे को पोषणयुक्त बनाने का प्रस्ताव रखा। एफएसएसआई को पोषणयुक्त खाद्य की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया।
- **न्यू इंडिया@75:** मुख्य खाद्य पदार्थों की अनिवार्य पोषणता और आईसीडीएस, पीएम पोषण और टीपीडीएस जैसे सरकारी कार्यक्रमों में उनके समावेश का समर्थन किया गया।
- **2019-2022:** 174.64 करोड़ रुपए के बजट के साथ केंद्र प्रायोजित पायलट योजना का शुभारंभ किया गया। मार्च 2022 तक 11 राज्यों में 4.30 लाख मीट्रिक टन पोषणयुक्त चावल वितरित किए गए।
- **अगस्त 2021:** प्रधानमंत्री ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में चावल को पोषणयुक्त बनाने की घोषणा की।

- **2022: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)** ने 4269.76 करोड़ रुपये के प्रस्तावित व्यय के साथ 30.06.2024 तक केंद्रीय पहल (100 प्रतिशत भारत सरकार की निधि) के रूप में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत पोषणयुक्त चावल की चरणबद्ध राष्ट्रीय आपूर्ति और आपूर्ति को स्वीकृति दी।
- चरण-I (2021-2022): एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) और पीएम पोषण को शामिल किया गया।
  चरण-II (2022-2023): 291 जिलों में टीपीडीएस (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली) और ओडब्ल्यूएस (अन्य कल्याणकारी योजनाएं) को जोड़ा गया।
  चरण-III (2023-2024): शेष जिलों तक विस्तारित किया गया।

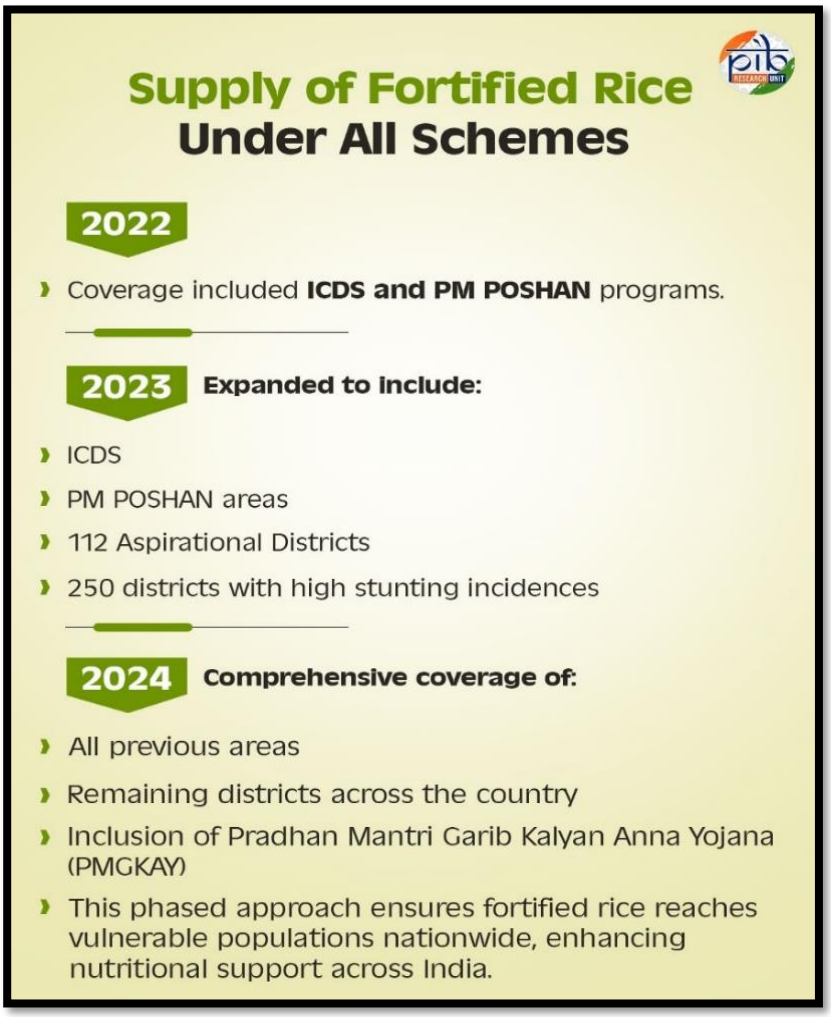

- **मार्च 2024:** सरकार की सभी योजनाओं के तहत पोषणयुक्त चावल के वितरण का 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और कस्टम-मिल्ड चावल को पोषणयुक्त चावल से बदल दिया गया है।

सरकार की हर योजना में कस्टम-मिल्ड चावल को पोषणयुक्त चावल से बदल दिया गया है और मार्च, 2024 तक पोषणयुक्त चावल के वितरण का 100 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है।

भारत में पोषणयुक्त खाद्य

फोर्टिफिकेशन भोजन को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों, जैसे विटामिन और खनिजों से समृद्ध करने की प्रक्रिया है, ताकि इसके पोषण की गुणवत्ता में सुधार हो सके। खाद्य फोर्टिफिकेशन का उपयोग दुनिया भर में वंचित आबादी में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय के रूप में किया जाता है। 2008 कोपेनहेगन कन्सेन्सस के अनुसार, खाद्य फोर्टिफिकेशन

विकासशील देशों के लिए शीर्ष तीन प्राथमिकताओं में से एक है और कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में, फोर्टिफिकेशन अतीत में सफल साबित हुआ है। उदाहरण के लिए, आयोडीन युक्त नमक ने आयोडीन की कमी और घेंघा जैसी बीमारियों को काफी हद तक कम कर दिया है।[1]

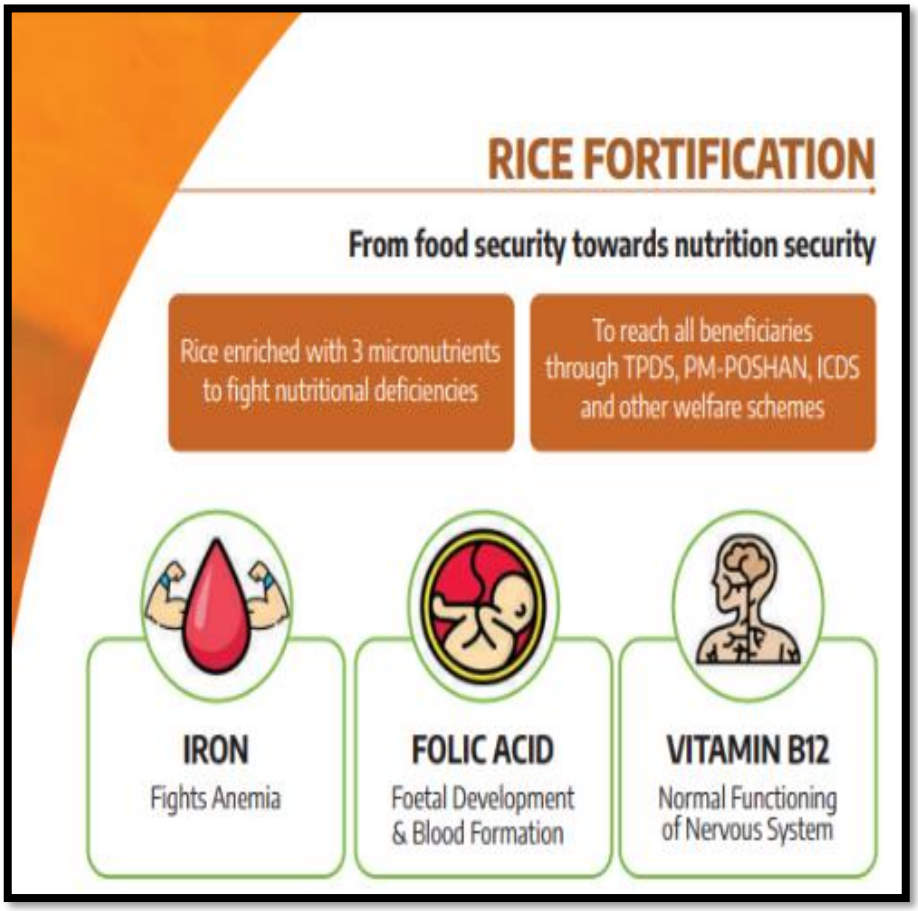

वर्ष 2019 और 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार, भारत में एनीमिया एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। आयरन की कमी के अलावा, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड जैसी अन्य विटामिन-खनिज की कमी भी बनी हुई है। यह आबादी के स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करती है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें फोर्टिफाइड चावल का वितरण भी शामिल है। भारत में, चावल 65 प्रतिशत आबादी का मुख्य भोजन है। यह आवश्यक पोषक तत्व को पूरा करता है। इस प्रक्रिया में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करते हुए नियमित कस्टम-मिल्ड चावल में फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) जोड़ना शामिल है। चावल फोर्टिफिकेशन के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य लाखों लोगों, विशेषकर अल्पपोषित लोगों के पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने में तेजी लाना है।

1 https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/jul/doc2024728356501.pdf
2 https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1826884&reg=3&lang=1

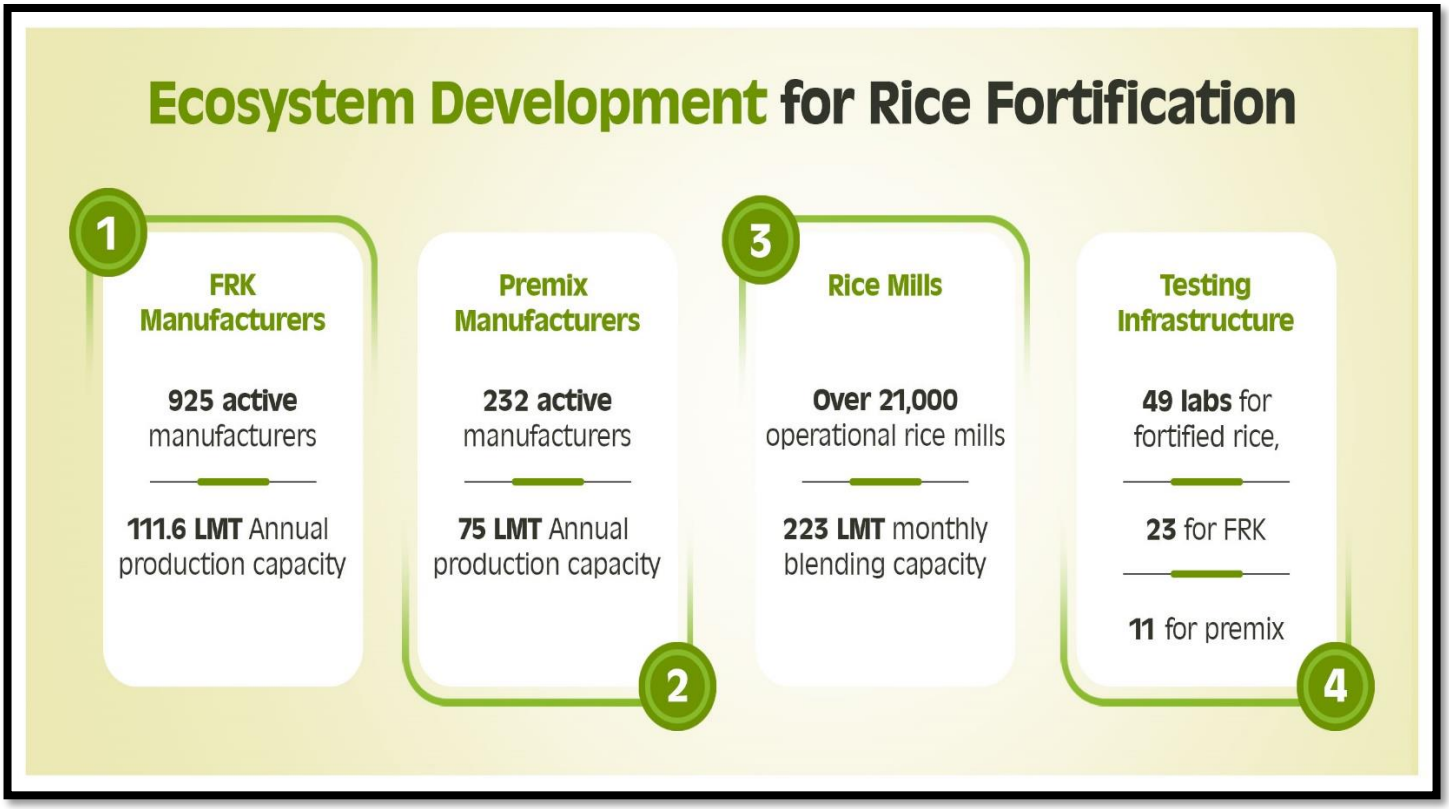

भारत में पोषण वृद्धि

फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के अलावा, भारत सरकार ने देश भर में पोषण संबंधी सेवन बढ़ाने और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये पहल कुपोषण के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती हैं और विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए सीधे पोषण संबंधी हस्तक्षेप पर जोर देती हैं।

प्रमुख पोषण योजनाएँ:

- पोषण अभियान:

वर्ष 2018 से, पोषण माह (समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना) और पोषण पखवाड़ा पूरे देश में आयोजित किया गया है, जिससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में वृद्धि हुई है। इन आयोजनों का उद्देश्य पोषण और स्वस्थ भोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पोषण माह 2024 में विशेष रूप से पोषण से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया, जिसमें स्वस्थ भोजन व्यवहारों को बढ़ावा देने, आहार विविधता में सुधार और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों के बारे में समुदायों को शिक्षित करने के लिए समर्पित 97.69 लाख गतिविधियां शामिल हैं।[2]

[2] https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153204&ModuleId=3&reg=3&lang=1

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई):**

  यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य मजदूरी हानि की मुआवजा और गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण और आराम को प्रोत्साहित करना है।

- **एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस):**

2 अक्टूबर, 1975 को शुरू की गई इस व्यापक योजना में लाभार्थियों को पूरक पोषण प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं और किशोरियों के लिए योजना शामिल है। योजना यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक आहार कार्यक्रमों के माध्यम से पर्याप्त पोषण मिले।

- **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण):**

पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाने जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति को बढ़ाना है, जिससे उनके शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास में सहायता मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए स्कूलों में राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस पहल के लिए वित्तीय आवंटन में केंद्र सरकार से 54,061.73 रुपये करोड़ और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से 31,733.17 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार खाद्यान्न के लिए लगभग 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी। परिणामस्वरूप, योजना का कुल बजट 130,794.90 करोड़ रुपये होगा।[3]

- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई):**

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। इस पहल का लक्ष्य लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है[4]

निष्कर्ष

एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए कैबिनेट की मंजूरी कुपोषण को संबोधित करने और लाखों लोगों की भलाई को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश के सभी रूपों में कुपोषण को समाप्त करने के सतत विकास लक्ष्य 2 को प्राप्त करने के प्रयास के रूप में, भारत का चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम पोषण संबंधी एनीमिया से निपटने के लिए सबसे प्रभावी पूरक हस्तक्षेपों में से एक है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले चावल द्वारा

[3] https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151969&ModuleId=3&reg=3&lang=1
[4] https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151969&ModuleId=3&reg=3&lang=1

सरकार का लक्ष्य वंचितों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना और एक मजबूत, स्वस्थ भारत को बढ़ावा देना है।[5]

संदर्भ

- https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151969&ModuleId=3&reg=3&lang=1
- https://x.com/PIB_India/status/1843952659071676501 (Graphics about Data)
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2063446
- https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1779256
- https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/jul/doc2024728356501.pdf
- https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1998748&reg=3&lang=1
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1746062 (PM Speech 75th Independence Day)

- **एमजी/आरपीएम/केसी/एसएस/एचएन/ओपी/एसके**

[5] https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2063446